

Daily News Analysis



- उर्वरक समिति की रिपोर्ट
- नक्सलवाद के उन्मूलन हेतु कार्यनीति
- भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति
- मत्स्यिकी क्षेत्र पर संसदीय समिति की रिपोर्ट
- AI-वॉशिंग: सच्चाई या दिखावा?
- Prelims Fact (short News)

25 March 2025, 8 AM



THE HINDU

 **The Indian EXPRESS**
JOURNALISM OF COURAGE

Indian Business Times
DELIVERING INDIAN BUSINESS STORIES



businessline.

**परीक्षा उपयोगी न्यूज और
एडिटोरियल की हिंदी व्याख्या**

Short News

1. AI-वॉशिंग: सच्चाई या दिखावा?
2. नई सुपर बैटरी: सूरज की रोशनी और हवा से चार्ज!
3. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025: कौन सबसे खुश, कौन सबसे पीछे?
4. म्यूनिसिपल बॉण्ड: शहरी विकास के लिए फंडिंग का स्मार्ट तरीका!
5. ऑर्गेनोमेटेलिक अणु: विज्ञान की नई खोज!
6. एंटी-डंपिंग शुल्क: घरेलू उद्योगों का सुरक्षा कवच

News Analysis

1. उर्वरक समिति की रिपोर्ट: कृषि क्षेत्र पर प्रभाव
2. नक्सलवाद के उन्मूलन हेतु भारत की कार्यनीति ☹️
3. भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति: नई लहरों की ओर
4. भारत में मत्स्यिकी क्षेत्र पर संसदीय समिति की रिपोर्ट: प्रमुख बिंदु और सिफारिशें

1. 📌 AI-वॉशिंग: सच्चाई या दिखावा? 🧐

EXPRESS OPINION

EDITORIALS COLUMNS

NEWS / OPINION / COLUMNS / Everyone seems to be claiming they use AI. But are they?

Opinion by

Everyone seems to be claiming they use AI. But are they?

AI washing misleads consumers by exaggerating or falsely claiming its use. As regulators enforce laws to mitigate AI-related harms, it is crucial to simultaneously enhance AI literacy of these bodies

🚀 क्या है AI-वॉशिंग?

- ✓ जब कंपनियाँ अपने उत्पादों या सेवाओं में **AI के उपयोग को बढ़ा-चढ़ाकर** या **गलत तरीके से पेश** करती हैं, तो इसे **AI-वॉशिंग** कहा जाता है।
- ✓ यह **"ग्रीनवॉशिंग"** से प्रेरित शब्द है, जहाँ कंपनियाँ अपनी सेवाओं को **अतिरिक्त पर्यावरण-अनुकूल** दिखाने का प्रयास करती हैं।

⚠️ AI-वॉशिंग के उदाहरण:

- ✗ **सिर्फ ऑटोमेशन को AI बताना** – असली AI के बजाय साधारण ऑटोमेटेड सिस्टम को "AI-पावर्ड" कहना।
- ✗ **बिना ठोस तकनीक के बड़े दावे** – AI के गहरे उपयोग के बिना भी "AI-संचालित" जैसे बज़वर्ड्स का इस्तेमाल।
- ✗ **AI का झूठा प्रभाव** – ऐसे उत्पाद पेश करना, जो AI का उपयोग करते ही नहीं, लेकिन दावा किया जाता है।

💰 स्टार्टअप और निवेश का खेल

- ⚡ **वेंचर कैपिटलिस्ट्स** इस प्रवृत्ति से चिंतित हैं, क्योंकि **स्टार्टअप्स फंडिंग पाने के लिए** AI से जुड़ी **गुमराह करने वाली रणनीतियाँ** अपनाते हैं।

🔍 AI-वॉशिंग से बचने के उपाय

- ✓ कंपनियों को **स्पष्ट पारदर्शिता** रखनी चाहिए।

- ✓ निवेशकों को तकनीकी दावों की जाँच करनी चाहिए।
- ✓ उपयोगकर्ताओं को वास्तविक AI और मार्केटिंग ट्रिक्स में फर्क समझना चाहिए।

🤖 AI या सिर्फ मार्केटिंग? सावधानी से पहचानें! 🚀

UPSC IAS 2026 प्रवेश प्रारंभ- 8 March 2025

फाउंडेशन कोर्स

इंटीग्रेटेड (प्रीलिम्स, मेंस और मेंटरशिप के साथ)

हिंदी माध्यम | ऑनलाइन लाइव बैच

₹25000 **₹14999**

KREDOZ The Learning App
Visit : www.kredoZ.com

7042389495, 9582225699

kredoZ IAS

फाउंडेशन के साथ
मेंटरशिप फ्री



2. ⚡ नई सुपर बैटरी: सूरज की रोशनी और हवा से चार्ज! 🌞👍

Ministry of Science & Technology



Redefining energy storage with photo-assisted, self-charging energy storage devices

Posted On: 19 MAR 2025 4:41PM by PIB Delhi

Researchers have unveiled a novel air-chargeable battery for a sustainable power solution. This technology traps the oxygen from the environment to drive the charging process for energy storage and is a step towards a carbon-neutral future.

In a world racing toward renewable energy solutions, a photo-assisted battery offers great promise as they combine the best of two worlds-- the light-capturing capability of solar cells and the robust energy storage of conventional batteries. Generally, solar panels convert sunlight into electricity, but they rely on separate battery systems to store the energy for later use. In contrast, photo-assisted batteries merge these functions into a single device, creating a seamless synergy between solar energy conversion and storage.

Photo-assisted batteries enhance the capacity of the batteries in the presence of light. However, it needs an external power supply to charge the battery. To overcome this limitation, there is an urgent requirement to develop energy storage devices with self-rechargeability.

Recent research has explored the "air-assisted self-charging" concept of aqueous ZIBs, aiming to utilize oxygen from the air to replenish the charge of the battery.

Researchers from the Centre for Nano and Soft Matter Sciences (CeNS), an autonomous institution under the Department of Science and Technology (DST) in Bengaluru,

📖 क्या खास है इस बैटरी में?

- ✓ **दोहरी चार्जिंग:** यह बैटरी सौर ऊर्जा और वायुमंडलीय ऑक्सीजन दोनों से खुद को चार्ज कर सकती है!
- ✓ **तेज चार्जिंग:** सिर्फ 140 सेकंड में 0.9V तक चार्ज हो जाती है।
- ✓ **ज्यादा पावर:** सामान्य बैटरियों से 170% अधिक ऊर्जा भंडारण क्षमता।

🚗 इसका उपयोग कहाँ हो सकता है?

- 🌱 **ग्रीन एनर्जी स्टोरेज** – पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत।
- 🚗 **इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ** – कम चार्जिंग समय, ज्यादा बैकअप।
- 🏠 **ऑफ-ग्रिड बिजली समाधान** – जहाँ बिजली नहीं पहुँचती, वहाँ भी उपयोगी।

⚠️ चुनौतियाँ:

- 💰 बड़े पैमाने पर उत्पादन किफायती होगा या नहीं?
- 🌤️ अलग-अलग मौसम में परफॉर्मेंस कैसा रहेगा?

✨ भविष्य की उम्मीद:

अगर यह तकनीक सफल रही, तो यह **बैटरियों की दुनिया में क्रांति ला सकती है!** ⚡📱



UPPCS 2024
मुख्य परीक्षा कोर्स
सम्पूर्ण पाठ्यक्रम (पेपर 1 से 6 तक)
120 Days फ्री मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन

कुल 700 घंटे की
लाइव क्लास |
Test Series

क्रेडो IAS

Q&A gni mes J arT-S0038X
mpo.roboXwww : RaTV

3. 😊 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025: कौन सबसे खुश, कौन सबसे पीछे? 🌍 ✨

News / World / Finland tops World Happiness rankings again; India ranks below Pakistan

Finland tops World Happiness rankings again; India ranks below Pakistan

Meanwhile, the United States recorded its lowest-ever position, ranking 24th.

By: **Express Web Desk**
March 20, 2025 13:50 IST

NewsGuard

🕒 3 min read



ADVERTISEMENT

Convenient banking,
Powered by innovation and trust!

Genext Banking With Human Touch

J&K Bank

📅 कब जारी हुई?

📍 20 मार्च (वर्ल्ड हैप्पीनेस डे) को **ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर**, गैलप और संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास समाधान नेटवर्क (UNSDSN) द्वारा।

सबसे खुशहाल देश:

 **फिनलैंड** (लगातार 8वें साल टॉप पर)

 डेनमार्क

 आइसलैंड

 स्वीडन

IN भारत की स्थिति:

 **2024:** 126वीं रैंक

 **2025:** 118वीं रैंक (8 पायदान की छलांग!)

दक्षिण एशियाई देशों की रैंकिंग:

✓ नेपाल – 92वाँ

✓ पाकिस्तान – 109वाँ

✗ म्याँमार – 126वाँ

✗ श्रीलंका – 133वाँ

✗ बांग्लादेश – 134वाँ

सबसे दुखी देश:

 **अफगानिस्तान (147वाँ) – लगातार चौथे साल सबसे नीचे**

 सिएरा लियोन (146वाँ), लेबनान (145वाँ), मलावी (144वाँ), ज़िम्बाब्वे (143वाँ)

कैसे तय होती है हैप्पीनेस रैंकिंग?

 3 साल के औसत डेटा के आधार पर लोग अपने जीवन को **0 से 10 के पैमाने पर रेट** करते हैं।

6 मुख्य फैक्टर्स:

✓ प्रति व्यक्ति GDP

✓ सामाजिक समर्थन

✓ स्वस्थ जीवन प्रत्याशा

✓ स्वतंत्रता

✓ उदारता

✓ भ्रष्टाचार की धारणा

क्या चीज़ें खुशी को बढ़ाती हैं?

 विश्वास और सामाजिक संबंध

🍲 साझा भोजन और सामुदायिक सहयोग

💖 दयालुता और परोपकार (पैसे से भी ज्यादा ज़रूरी!)

🌸 **वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की शुरुआत:**

BT **भूटान की पहल** – 1970 के दशक से ही **GDP से ज्यादा ग्राँस नेशनल हैप्पीनेस (GNH)** को महत्व देता है।

🇨🇦 **संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में इसे आधिकारिक मान्यता दी।**

🌟 **2025 की थीम: "केयरिंग एंड शेयरिंग"** 🌸



UPPCS 2024 MAINS

उत्तर लेखन कार्यक्रम

कुल 120 टेस्ट | प्रति टेस्ट 7 प्रश्न

प्रवेश प्रारंभ
हिंदी | English |
मॉडल उत्तर | वीडियो
डिस्कशन

**7042389495,
9582225699**



KRED02: The Learning App
Visit: www.kredozias.com

4. 🏙️ **म्यूनिसिपल बॉण्ड: शहरी विकास के लिए फंडिंग का स्मार्ट तरीका!**



Companies / Markets / Portfolio / Opinion / Economy / **bl PREMIUM**

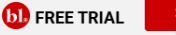
Home » Data Stories » Visually

Why municipal bonds are not taking off

Updated - March 20, 2025 at 10:16 PM.

Since FY18, around 17 municipal bonds worth ₹2,600 crore have been issued, with an average size of ₹150 crore, according to the recent ICRA report. These securities are slow to take off despite more than 10 issuances for raising over ₹1,500 crore expected in FY26.

BY BL DATA TEAM



FREE TRIAL

Search Stock Quotes, News, Mutual F

💎 **क्या हैं बॉण्ड?**

📄 बॉण्ड एक **ऋण साधन** हैं, जहाँ निवेशक अपनी पूँजी उधार देते हैं और इसके बदले ब्याज कमाते हैं।

📊 **प्रमुख प्रकार:**

✓ **ट्रेजरी बॉण्ड** 🏛️ (सरकार द्वारा जारी)

✓ **म्यूनिसिपल बॉण्ड** 🏙️ (शहरों के विकास हेतु)

- ✓ कॉर्पोरेट बॉण्ड 🏢 (कंपनियों द्वारा जारी)
- ✓ फ्लोटिंग रेट बॉण्ड ☑️ (ब्याज दर बदलती रहती है)
- ✓ ज़ीरो-कूपन बॉण्ड 🕒 (ब्याज नहीं, परिपक्वता पर पूरा भुगतान)

🏠 **म्यूनिसिपल बॉण्ड क्या हैं?**

👉 शहरी विकास परियोजनाओं के लिए स्थानीय नगर निकायों (ULB) द्वारा जारी ऋण साधन।

🏠 पानी, सीवरेज, नवीकरणीय ऊर्जा और सड़क निर्माण जैसी परियोजनाओं के लिए उपयोग।

🌟 **लाभ:**

- ✓ सरकारी फंड पर कम निर्भरता 🏠
- ✓ वित्तीय स्वतंत्रता में वृद्धि 📈
- ✓ निजी निवेश आकर्षित करना 🤝
- ✓ शहरी बुनियादी ढाँचे में सुधार 🏗️

⚠️ **चुनौतियाँ:**

- ✗ राज्य सरकार के अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता (FY24 में ULBs का **38% राजस्व**)
- ✗ बहुत कम शहरों ने बॉण्ड जारी किए (पुणे, अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद, लखनऊ)
- ✗ निवेशकों के लिए सीमित आकर्षण और पारदर्शिता की कमी

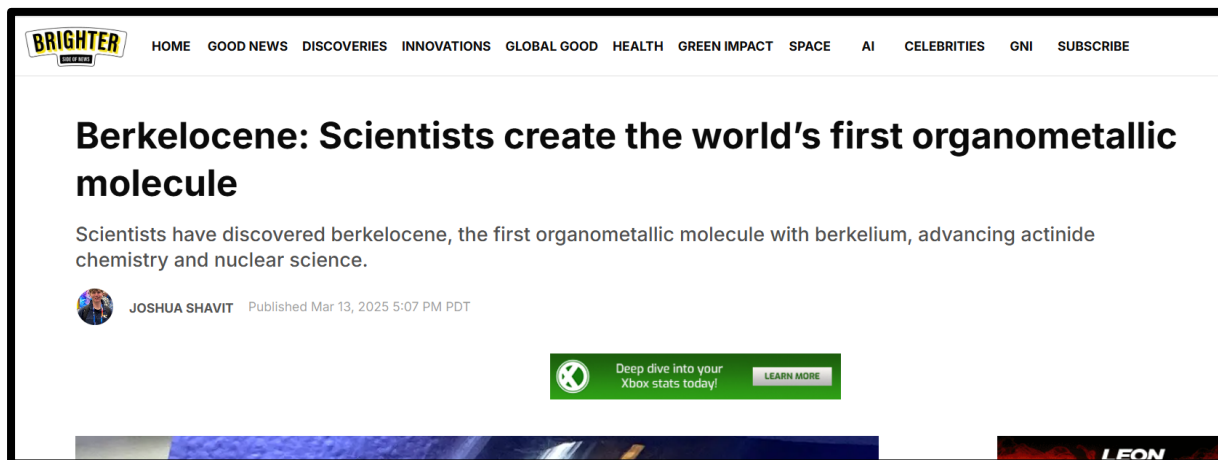
📊 **कैसे बढ़ेगा म्यूनिसिपल बॉण्ड का उपयोग?**

- ✓ सरल नियम व प्रक्रियाएँ 🏠
- ✓ शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार ☑️
- ✓ ऋण वृद्धि उपायों को अपनाना 💰
- ✓ टैक्स इंसेंटिव और द्वितीयक बाजार का विकास 🏢

💡 **क्या यह भारत में सफल होगा?**

अगर ULB की पारदर्शिता, नियामकीय सुधार और बेहतर वित्तीय प्लानिंग को मजबूत किया जाए, तो म्यूनिसिपल बॉण्ड भारत के शहरों के लिए गेमचेंजर साबित हो सकते हैं! 🚀

5. 🏠 ऑर्गेनोमेटेलिक अणु: विज्ञान की नई खोज! ✨



❖ क्या हैं ऑर्गेनोमेटेलिक अणु?

- ✓ वे यौगिक जिनमें कार्बन और धातु के बीच सीधा बंध होता है।
- ✓ धातु और कार्बन दोनों के गुण मौजूद होते हैं।

✨ नई खोज: बर्केलोसीन ✨

🏠 वैज्ञानिकों ने पहला ऑर्गेनोमेटेलिक अणु 'बर्केलोसीन' खोजा, जिसमें भारी तत्व बर्केलियम (Bk) शामिल है।

☒ गुणधर्म:

- ✓ संवेदनशीलता – हवा या नमी से प्रभावित हो सकते हैं।
- ✓ उष्मा सहनशीलता – कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक गर्मी सहन कर सकते हैं, पर तापमान के अनुसार गुण बदल सकते हैं।
- ✓ विद्युत चालकता – कुछ अणु बिजली का संचालन कर सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोगी।
- ✓ उत्प्रेरक के रूप में कार्य – रासायनिक अभिक्रियाओं को गति देते हैं पर स्वयं खपत नहीं होते।

✨ अनुप्रयोग:

- ❖ इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग (सुपरकंडक्टर, ट्रांजिस्टर)
- ❖ औद्योगिक उत्प्रेरक (पेट्रोलियम उद्योग)
- ❖ दवा निर्माण (औषधीय अनुसंधान में उपयोग)

💡 क्या ये विज्ञान का भविष्य हैं?

बर्केलोसीन जैसी खोजें रसायन और भौतिकी के लिए नए दरवाजे खोल सकती हैं! 🚀



Kredoz IAS

क्या -2 कवर होगा ?

- सामान्य हिंदी**
 - GS-01 कला एवं संस्कृति, इतिहास, भूगोल, भारतीय समाज
 - GS-05 उत्तर प्रदेश विशेष
- निबंध (Essay)**
 - GS-02 भारतीय राजतन्त्र, गवर्नंस, अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध
- सामान्य अध्ययन**
 - GS-03 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, आपदा प्रबंध, विज्ञान एवं अंतरिक्ष सुरक्षा
 - GS-04 नीतिशास्त्र
 - GS-06 उत्तर प्रदेश विशेष

UPPSC 2025 फाउंडेशन कोर्स

इंटीग्रेटेड (प्रीलिम्स, मेंस और मेंटरशिप के साथ)

हिंदी माध्यम | ऑनलाइन लाइव बैच

📞 **7042389495, 9582225699** Download Kredoz the Learning app

6. 🏠 एंटी-डंपिंग शुल्क: घरेलू उद्योगों का सुरक्षा कवच 🛡️



⚡ क्या है एंटी-डंपिंग शुल्क?

- ✓ जब कोई देश किसी वस्तु को **उसकी वास्तविक लागत से कम कीमत पर** किसी दूसरे देश में बेचता है, तो इसे **डंपिंग** कहते हैं।
- ✓ इस अनुचित व्यापार से बचाव के लिए **भारत ने चीन से आयातित कई वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क** लगाया है।

⚡ एंटी-डंपिंग शुल्क क्यों ज़रूरी?

- ◆ **घरेलू उद्योगों की रक्षा** – सस्ते आयात से स्थानीय उत्पादकों को बचाना।
- ◆ **अनुचित प्रतिस्पर्धा रोकना** – कंपनियों को बाज़ार में टिकाऊ बनाए रखना।
- ◆ **प्रिडेटरी प्राइसिंग से बचाव** – जब कोई कंपनी जानबूझकर **अत्यधिक कम दाम** पर सामान बेचकर प्रतियोगियों को बाज़ार से बाहर कर देती है।

🌐 WTO के नियम क्या कहते हैं?

- 📄 **GATT 1994** का अनुच्छेद VI एंटी-डंपिंग शुल्क की अनुमति देता है।
- 📄 किसी भी शुल्क को लगाने से पहले **डंपिंग के प्रमाण, स्थानीय उद्योग पर प्रभाव**, और

दोनों के बीच संबंध को साबित करना ज़रूरी है।

📖 एंटी-डंपिंग उपाय **अस्थायी होते हैं** और समय-समय पर **समीक्षा** की जाती है।

⚠️ **भारत की स्थिति**

- ◆ चीन से स्टील, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उत्पादों पर **एंटी-डंपिंग शुल्क** लगाया गया है।
- ◆ सरकार ऐसे शुल्कों का उपयोग कर **घरेलू कंपनियों को वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखने** की कोशिश कर रही है।

🔍 **क्या एंटी-डंपिंग शुल्क हमेशा सही है?**

- ✅ हाँ, यदि यह घरेलू उद्योगों को बचाता है।
- ❌ नहीं, अगर यह उपभोक्ताओं पर अधिक मूल्य का बोझ डालता है।

😊 **क्या यह भारत के लिए फायदेमंद है?**

👉 हाँ! यदि सही तरीके से लागू किया जाए, तो यह **स्थानीय अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाता है और व्यापार को संतुलित रखता है**। 🚀

News Analysis

1. 🌾 **उर्वरक समिति की रिपोर्ट: कृषि क्षेत्र पर प्रभाव** 📊



The screenshot shows a news article from The Hindu. The headline is "Fertilizers committee warns against under-funding of nutrient subsidy schemes". Below the headline, it says "The report also notes the improvement in selected crop growth with modern fertilizers; urges the Centre to develop domestic production capabilities." The article is dated "Published - March 23, 2025 12:02 am IST - New Delhi". The source is "THE HINDU BUREAU". There are also links for "FREE TRIAL", "SUBSCRIBE", and "LOGIN" at the top right.

🔗 **क्या है मामला?**

- ✅ 2025-26 के लिए उर्वरक विभाग ने 1.84 लाख करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने 7% की कटौती कर दी।
- ✅ इस कटौती का असर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना और यूरिया सब्सिडी योजना दोनों पर पड़ा है।

▲ प्रमुख चिंताएँ

- ◆ **उर्वरक सुरक्षा पर खतरा** – भू-राजनीतिक तनाव और कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण DAP (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) जैसी आवश्यक उर्वरकों की कमी हो रही है।
- ◆ **प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं** – फॉस्फेट और पोटाश जैसे आवश्यक कच्चे माल के लिए खनन पट्टों की कोई पहल नहीं हुई।
- ◆ **उर्वरक ग्रेड का असंतुलन** – NPKS उर्वरकों के उचित ग्रेड सभी क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हैं, जिससे किसानों का अतिरिक्त खर्च बढ़ता है।
- ◆ **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) में खामियाँ** – सही लाभार्थियों की पहचान में समस्या, जिससे घोटालों का खतरा।
- ◆ **नैनो उर्वरकों पर सीमित शोध** – नैनो यूरिया और नैनो DAP कृषि उत्पादन बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी अधिक शोध की जरूरत।

📢 समिति की सिफारिशें

- ◆ **आपूर्ति प्रबंधन और संतुलित उर्वरक वितरण** – मृदा परीक्षण के आधार पर सही उर्वरक का वितरण सुनिश्चित किया जाए।
- ◆ **FCEWS प्रणाली की स्थापना** – उर्वरक संकट पूर्व चेतावनी प्रणाली (FCEWS) बनाई जाए, जिससे आपूर्ति बाधा से पहले ही समाधान खोजा जा सके।
- ◆ **AADHAAR लिंकिंग** – किसानों की पहचान के लिए आधार को किसान रजिस्ट्रेशन से जोड़ा जाए, जिससे जोत के आकार के अनुसार उर्वरक खरीद की सीमा तय की जा सके।
- ◆ **यूरिया गोला का उपयोग** – पारंपरिक यूरिया की जगह यूरिया गोला को बढ़ावा देना, जिससे उर्वरकों का कुशल उपयोग हो सके।

🌿 पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) नीति

- ✓ **सब्सिडी दरें:** नाइट्रोजन (N), फॉस्फेट (P), पोटाश (K), और सल्फर (S) के लिए निर्धारित सब्सिडी।
- ✓ **कवरेज:** इसमें DAP, MAP (मोनो अमोनियम फॉस्फेट), और MOP (म्युरेट ऑफ पोटाश) सहित 28 प्रकार के P&K उर्वरक शामिल।
- ✓ **MRP में लचीलापन:** उर्वरक कंपनियाँ MRP निर्धारित करती हैं, लेकिन सरकार कीमतों की समीक्षा कर सकती है।
- ✓ **अतिरिक्त सब्सिडी:** बोरॉन और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए अलग से सब्सिडी।

🌾 यूरिया सब्सिडी योजना

✧ **उद्देश्य:** किसानों को किफायती दरों पर यूरिया उपलब्ध कराना, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

✧ **उत्पादन पर फोकस:** स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देकर यूरिया में आत्मनिर्भरता हासिल करना।

निष्कर्ष

सरकार को कृषि उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरक सब्सिडी की कटौती पर पुनर्विचार करना चाहिए। मृदा स्वास्थ्य, नैनो उर्वरकों का विकास और सब्सिडी वितरण में सुधार से किसानों को अधिक लाभ मिल सकता है। 🌱

2. **नक्सलवाद के उन्मूलन हेतु भारत की कार्यनीति**



Ministry of Home Affairs

Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah says, under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, Central Government is moving forward with a ruthless approach against the Naxalites

Security forces neutralizes 22 Naxalites in two separate operations in Chhattisgarh

Today our jawans have achieved another big success in the direction of a 'Naxalmukt Bharat Abhiyan'

The Modi government is adopting a zero-tolerance policy against those Naxalites who are not surrendering despite all the facilities being offered to them, ranging from surrender to inclusion

✧ **चर्चा में क्यों?**

✓ केंद्रीय गृह मंत्री ने **31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य** घोषित किया है।

✓ इसका उद्देश्य **नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और विकास को बढ़ावा देना** है।

भारत की रणनीति: बहुआयामी दृष्टिकोण

विकास कार्यक्रम

✧ **राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना, 2015:**

- सुरक्षा उपायों, विकास पहलों और सामुदायिक अधिकार संरक्षण को शामिल करता है।

✧ महत्वपूर्ण योजनाएं:

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना II:** नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाना।
- **रोशनी योजना:** प्रभावित जिलों के युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर।
- **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS):** जनजातीय छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।
- **सार्व सेवा दायित्व निधि योजना (डिजिटल भारत निधि):** मोबाइल टावरों की स्थापना।
- **नेहरू युवा केंद्र संगठन:** जनजातीय युवाओं के लिए संपर्क और जागरूकता कार्यक्रम।

2 सुरक्षा अभियान

✧ विशेष अभियानों का संचालन:

- **ऑपरेशन ग्रीन हंट:** बड़े पैमाने पर नक्सल विरोधी अभियान।
- **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF), CoBRA, ग्रेहाउंड्स** की तैनाती।
- **रेड कॉरिडोर में आतंकवाद के उन्मूलन के लिए सुरक्षा बलों की उपस्थिति बढ़ाना।**

3 विधिक ढाँचा

✧ कानूनी कार्रवाई:

- **UAPA, 1967:** CPI (माओवादी) और अन्य संगठनों पर प्रतिबंध।
- **वन अधिकार अधिनियम, 2006:** जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा।
- **PESA, 1996:** जनजातीय ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना।

4 आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति

✓ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को:

- **वित्तीय सहायता** 
- **व्यावसायिक प्रशिक्षण** 

- सामाजिक पुनर्कीकरण कार्यक्रम 🏠

◆ अब तक की प्रगति 📊

✈ 2014 बनाम 2024:

- नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या: 126 → 12 ☑
- नक्सल घटनाएँ: 16,463 → 7,700 ☑
- सुरक्षा बलों की हताहत संख्या में कमी: 73% ☑
- नागरिक हताहतों की संख्या में कमी: 70% ☑
- फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन: 66 → 612 ☑

◆ नक्सलवाद: एक परिचय 📄

✓ **शुरुआत:** 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव से।

✓ **प्रेरणा:** माओवादी विचारधारा और गुरिल्ला युद्ध।

✓ **प्रमुख कारण:**

- भूमि वितरण में असमानता।
- गरीबी और विकास की कमी।
- औद्योगीकरण और खनन परियोजनाओं से विस्थापन।
- पुलिस और प्रशासन की ज्यादतियाँ।

✓ **मुख्य संगठन:**

- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) – सबसे हिंसक गुट।
- UAPA, 1967 के तहत प्रतिबंधित।

✓ **प्रभावित क्षेत्र:**

- "रेड कॉरिडोर" (छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार आदि)।

◆ निष्कर्ष 🇮🇳

✈ भारत की **सुरक्षा, विकास और पुनर्वास पर केंद्रित रणनीति** नक्सलवाद को समाप्त करने में प्रभावी साबित हो रही है।

✦ 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य संभव लग रहा है, लेकिन सतर्कता और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

👉 क्या आप मानते हैं कि यह रणनीति नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर सकती है? 🤔

3. भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति: नई लहरों की ओर 🇮🇳



भूमिका

भारत जल्द ही हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) की अध्यक्षता करेगा, जिससे उसे इंडो-पैसिफिक में अपनी भूमिका को मज़बूत करने का सुनहरा मौका मिलेगा। यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार का 75% संभालता है और दुनिया की दो-तिहाई आबादी को समेटे हुए है। लेकिन, बजटीय कमी, संस्थागत चुनौतियाँ और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा भारत के सामने बड़ी बाधाएँ हैं।

🔍 क्यों महत्वपूर्ण है हिंद-प्रशांत?

✓ सुरक्षा एवं रणनीतिक स्वायत्तता – चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत की समुद्री सुरक्षा प्रमुख चिंता है।

✓ आर्थिक विकास – IPEF, FTA और चाइना-प्लस-वन रणनीति के तहत व्यापार बढ़ाने के प्रयास।

✓ डिजिटल एवं भौतिक संपर्क – IMEC, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) और लॉजिस्टिक्स सुधार।

✓ ब्लू इकॉनमी एवं जलवायु नेतृत्व – समुद्री पारिस्थितिकी संरक्षण और हरित वित्त में अग्रणी भूमिका।

✓ सामरिक नेतृत्व – IORA अध्यक्षता के तहत ग्लोबल साउथ में प्रभाव बढ़ाने का प्रयास।

🇮🇳 भारत के सामने मुख्य चुनौतियाँ

- ✗ **सीमित सैन्य संसाधन** – चीन और अमेरिका की तुलना में भारत की नौसैनिक ताकत अभी सीमित।
- ✗ **स्पष्ट रणनीति की कमी** – SAGAR, एक्ट ईस्ट, IPOI जैसी पहलें अलग-अलग दिशा में बढ़ रही हैं।
- ✗ **रणनीतिक संतुलन की दुविधा** – QUAD, BRICS, SCO में संतुलन साधने की चुनौती।
- ✗ **आर्थिक अनिश्चितता** – RCEP से बाहर रहना और सीमित FTA भागीदारी।
- ✗ **संस्थागत कमजोरी** – IORA जैसे संगठनों में भारत की सक्रियता अभी धीमी।

📣 **भारत क्या कर सकता है?**

- ◆ **एकीकृत हिंद-प्रशांत रणनीति तैयार करे** – SAGAR, IPOI, IPEF को जोड़कर स्पष्ट दिशा दे।
- ◆ **नौसेना और समुद्री अवसंरचना को मजबूत करे** – गहरे बंदरगाह, जहाज निर्माण और MDA नेटवर्क का विस्तार।
- ◆ **IORA और BIMSTEC जैसे संगठनों में नेतृत्व बढ़ाए** – क्षेत्रीय सहयोग और कूटनीति को गति दे।
- ◆ **नई व्यापारिक साझेदारियाँ विकसित करे** – ASEAN, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध बनाए।
- ◆ **ब्लू इकॉनमी और हरित विकास में अग्रणी बने** – सस्टेनेबल समुद्री विकास और जलवायु कार्रवाई को प्रोत्साहित करे।

🎯 **निष्कर्ष**

भारत को **"नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर"** और **"इकोनॉमिक इंजन"** की भूमिका निभाने के लिए अपने **सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक प्रयासों को समेकित रूप से आगे बढ़ाना होगा।** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी से भारत वैश्विक शक्ति संतुलन में **केंद्र बिंदु** बन सकता है।



✧ **नया युग, नई दिशा – भारत, हिंद-प्रशांत की धड़कन!** IN ✧

4. भारत में मत्स्यिकी क्षेत्र पर संसदीय समिति की रिपोर्ट: प्रमुख बिंदु और सिफारिशें



परिचय:

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है, जिसका वैश्विक मत्स्य उत्पादन में 8% योगदान है। यह क्षेत्र रोजगार, खाद्य सुरक्षा और निर्यात आय में अहम भूमिका निभाता है। हाल ही में संसदीय स्थायी समिति ने इस क्षेत्र में सुधार के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें प्रमुख समस्याओं और सुधार के सुझावों को रेखांकित किया गया है।

मुख्य समस्याएँ

मत्स्यिकी के लिए अलग शोध संस्थान का अभाव:

वर्तमान में, मत्स्य अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अंतर्गत आता है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए अलग से कोई समर्पित राष्ट्रीय संस्थान नहीं है।

छोटी मछलियों (Juvenile Fish) के अंधाधुंध शिकार पर नियंत्रण की कमी:

ट्रॉलिंग (Trawling) और अवैध मछली पकड़ने की तकनीकों के कारण जलाशयों में मछलियों की संख्या तेजी से घट रही है।

मछुआरों को ब्याज मुक्त ऋण नहीं मिल पाना:

केवल कुछ राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर 4% ब्याज सब्सिडी दी जाती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है।

मछली पकड़ने के बाद खराब होने की समस्या (Post-Harvest Losses):

कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण और परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण लगभग 20-25% मछलियाँ बाजार तक नहीं पहुँच पातीं।

झींगा (Shrimp) उत्पादन में आत्मनिर्भरता की कमी:

भारत अभी भी L. Vannamei झींगा बीज (Broodstock) के आयात पर निर्भर है।

◆ बाँधों के गेट खुलने से मछलियों का नुकसान:

बाँधों के गेट खुलने से **नदी में मछली स्टॉक बह जाता है**, जिससे स्थानीय मछुआरों को नुकसान होता है।

◆ निर्यात में बाधाएँ:

कठोर **स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी (SPS) मानकों** के अनुपालन, प्रमाणन और ट्रेसबिलिटी की कमी के कारण भारत के मत्स्य निर्यात को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

◆ समिति की प्रमुख सिफारिशें

- ✓ मत्स्यिकी क्षेत्र के लिए एक समर्पित अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाए।
- ✓ छोटी मछलियों को बचाने के लिए कानूनी रूप से जालों के न्यूनतम आकार का नियम लागू किया जाए।
- ✓ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत मछुआरों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा दी जाए।
- ✓ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण और लॉजिस्टिक्स में सुधार किया जाए।
- ✓ ICAR के माध्यम से देश में ही ड्रींग बीज (Broodstock) उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए।
- ✓ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की तर्ज पर मछुआरों के लिए बीमा योजना शुरू की जाए।
- ✓ मत्स्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सर्टिफिकेशन और गुणवत्ता मानकों में सुधार किया जाए।

🌀 निष्कर्ष:

मत्स्यिकी क्षेत्र में सुधार के लिए **तकनीकी नवाचार, बेहतर वित्तीय सहायता और सख्त नियामक उपायों** की जरूरत है। समिति की सिफारिशें इस क्षेत्र में **रोजगार बढ़ाने, उत्पादन को स्थायी बनाने और वैश्विक निर्यात में भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने** में सहायक हो सकती हैं।

🚀 **यदि इन सुधारों को लागू किया जाता है, तो भारत मत्स्यिकी में आत्मनिर्भर बनने और वैश्विक निर्यात में अग्रणी बनने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा सकता है!** 🇮🇳